RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 25 AUGUST TO 31 AUGUST 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 52 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

इंडियन ऑयल ने पाइपलाइन से ईंधन चोरी रोकने का ढूंढ निकाला नया तरीका Page 2

पापड़ खरीद रहे हैं तो देना होगा GST Page 3

इन्फोसिस की बड़ी उपलब्धि 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप छूने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनी Page 5

editoria!

निर्यात पर ध्यान

अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा व्यापार घाटे में कमी लाने के लिए सरकार निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में लगी हुई है. इन प्रयासों को सफल बनाने में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है. इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वाकांक्षी योजना 'उभरते सितारे' की घोषणा की है. इसके तहत उन छोटे एवं मझोले उद्यमों को सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, भविष्य में जिनके उत्पादों के निर्यात की संभावना होगी. इस योजना का उल्लेख फरवरी में लाये गये बजट में ही था, किंतु कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पैदा हुई परिस्थितियों के कारण उसे पहले लागू नहीं किया जा सका था. बीते डेढ़ साल में कोरोना महामारी की मार सबसे अधिक छोटे और मझोले उद्यमों को ही सहनी पड़ी है, लेकिन इस क्षेत्र को राहत देने के लिए वित्त मुहैया कराने, कर्ज वसूली रोकने तथा नियमन में सुधार जैसी कोशिशें भी हुई हैं. इन कोशिशों ने एक बार फिर इस क्षेत्र में गतिविधियां तेज होने लगी हैं. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में निर्यात बढ़ा कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की ठोस उपस्थिति स्थापित करने का उद्देश्य भी शामिल है. कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के उद्योग जगत और संबंधित प्रतिष्ठानों से निर्यात बढ़ाने का आह्वान किया था. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक नीतिगत पहल की आवश्यकता है. 'उभरते सितारे' योजना ऐसी ही पहल का एक हिस्सा है. कुछ विकसित देशों में बहुत पहले ऐसे उद्यमों को चिह्नित किया गया, जो भविष्य में निर्यात बढ़ाने में योगदान दे सकते थे. उन्हें आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने के साथ उनकी तकनीकी क्षमता बढ़ाने में भी सरकारों ने मदद की. कुछ समय बाद इसका लाभ उन अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात वृद्धि के रूप में मिला. भारत सरकार की योजना ऐसे ही कार्यक्रमों से प्रेरित है. आम तौर पर यह देखा जाता है कि अनेक उद्यम अपनी संभावनाओं को पूरी तरह साकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास आवश्यक निवेश के लिए धन नहीं होता तथा तकनीक तक उनकी पहुंच आसान नहीं होती है. 'उभरते सितारे' योजना से इस अवरोध को दूर करने में बड़ी मदद मिल सकती है. भारत के लघु उद्योग विकास बैंक ने भी छोटे एवं मझोले उद्यमों को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए बहुआयामी सहायता देने की बड़ी योजना तैयार की है. इन पहलों से उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकेंगे. इससे देश के भीतर रोजगार और आमदनी बढ़ाने में भी सहयोग मिलेगा. देश के सकल घरेलू उत्पादन में छोटे और मझोले उद्यम की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है. 'उभरते सितारे' योजना इसे केंद्र सरकार के लक्ष्य 40 प्रतिशत तक ले जा सकती है. अभी इस क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोग काम करते हैं. उम्मीद करनी चाहिए कि विभिन्न उद्यम इस पहल का लाभ उठा कर निर्यात बढ़ाने में योगदान करेंगे.

कच्चा तेल फिर 71 डॉलर प्रति बैरल के पार, दाम में कोई तब्दीली नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

चीन में कोविड-19 के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसी के साथ मैक्सिको की खाड़ी में कच्चे तेल के उत्पादन में भारी कमी आई है। इससे मंगलवार को कच्चा तेल बाजार चढ़ गया। इस दिन कारोबार की समाप्ति पर ब्रेंट क्रूड में तीन फीसदी से भी ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। इसी के साथ एक बार फिर इसका दाम 71 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गया। हालांकि घरेलू मोर्चे पर देखें तो यहां आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। इससे एक दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में जहां 15 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई थी, वहीं डीजल भी 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया गया था। दिल्ली के बाजार में बुधवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल जहां 101.49 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर था, वहीं डीजल का दाम भी 88.92 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा।

इस साल मई से जुलाई के बीच 11.52 रुपये महंगा हो चुका है पेट्रोल

इस साल की पहली तिमाही के दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इसलिए, उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन, बीते चार मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी। कभी लगातार तो कभी ठहर कर, 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। हालांकि, हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद बीते 18 जुलाई से इसके दाम स्थिर थे। हालांकि रक्षा बंधन के दिन, इसके दाम में महज 20 पैसे की कमी की गई थी। उसके बाद कल 15 पैसे की कमी हुई है।

कुछ और सस्ता हुआ है डीजल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भले ही सस्ता बिक रहा हो, लेकिन यहां सरकारी तेल कंपनियां उस हिसाब से कीमतों में कमी नहीं कर रही हैं। वैसे भी डीजल महंगा ईंधन होने के बावजूद भारत में यह पेट्रोल के मुकाबले सस्ता बिकता है। इसकी वजह यह है कि यहां अधिकतर बस और ट्रक डीजल से ही चलते हैं। यदि यह ईंधन महंगा होता है तो बाजार में महंगाई तेजी से भड़कती है। इस साल की शुरूआती महीनों में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस दौरान 41 दिनों तक डीजल के दाम में कोई फेरदबल नहीं हुआ था। उस समय डीजल के दाम में अंतिम कमी बीते 15 अप्रैल को हुई थी। उस समय 14 पैसे की कमी हुई थी। लेकिन बीते 4 मई से इसमें जो ठहर-ठहर कर बढ़ोतरी हुई, उससे डीजल 9.08 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। उसके बाद बीते 16 जुलाई से इसके दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। बीते 18 अगस्त से 20 अगस्त तक इसकी कीमतों 20 पैसे प्रति लीटर की रोजाना कमी हुई है। इसके बाद रक्षा बंधन के दिन भी दाम में इतनी ही कमी हुई थी। कल भी यह 15 पैसे सस्ता हुआ था। इस तरह से अब तक डीजल 95 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो चुका है।

कच्चे तेल का बाजार लगातार दूसरे दिन रही तेजी

चीन में कोविड-19 के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसी के साथ मैक्सिको की खाड़ी में कच्चे तेल के उत्पादन में भारी कमी आने से मंगलवार को कच्चा तेल बाजार चढ़ गया। इस दिन कारोबार की समाप्ति पर ब्रेंट क्रूड में तीन फीसदी से भी ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। इससे पहले सोमवार को भी यह चढ़ा था। इन दो दिनों में ही ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल पांच डॉलर महंगा हो चुका है। इसी के साथ एक बार फिर इसका दाम 71 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गया। अमेरिकी बाजार में कल कारोबार की समाप्ति के समय ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 2.48 डॉलर प्रति बैरल चढ़ कर 71.05 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। इसी तरह डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 2.08 डॉलर प्रति बैरल तेज होकर 67.54 डॉलर पर बंद हुआ था।

जुलाई में देश का कच्चे तेल का उत्पादन 3.2 प्रतिशत गिरा

प्राकृतिक गैस उत्पादन में बढ़त

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के कच्चे तेल के उत्पादन में लगातार गिरावट जारी है, ओएनजीसी के द्वारा लक्ष्य से कम तेल उत्पादन की वजह से जुलाई में देश का क्रूड उत्पादन 3 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कच्चे तेल का उत्पादन जुलाई के दौरान पिछले साल के मुकाबले 3.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25 लाख टन के स्तर पर आ गया है। वहीं अप्रैल से जुलाई की अवधि में उत्पादन 3.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99 लाख टन रहा है।

देश के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक ओएनजीसी ने जुलाई के दौरान 16 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन किया। ये पिछले साल के मुकाबले 4 प्रतिशत कम है और कंपनी के द्वारा तय किये गये 17 लाख टन के लक्ष्य से 3.8 प्रतिशत कम रहा है। अप्रैल से जुलाई के बीच ओएनजीसी का तेल उत्पादन 4.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64 लाख टन रहा है। हालांकि दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस में बढ़त देखने को मिली है। रिलायंस बीपी के केजी डी6 तेल क्षेत्र में बेहतर उत्पादन की वजह से जुलाई में गैस उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 18.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2.9 बीसीएम (billion cubic meter) तक पहुंच गया। वहीं इस बढ़त की मदद से अप्रैल से जुलाई के बीच गैस उत्पादन 20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11 बीसीएम के स्तर पर पहुंच गया। ओएनजीसी फील्ड से गैस उत्पादन 10 प्रतिशत गिरा है. वहीं पूर्वी ऑफशोर जहां केजी डी6 फील्ड स्थित हैं गैस का उत्पादन 12 गुना बढ़कर 573.13 एमसीएम (million cubic meter) पर पहुंच गया है। मंत्रालय के मुताबिक गैस उत्पादन में बढ़त डी 34 के ब्लॉक से उत्पादन बढ़ने की वजह से दर्ज हुई है। इस ब्लॉक से 18 दिसंबर 2020 से उत्पादन शुरू हुआ है।

ईंधन की मांग में बढ़त के साथ तेल रिफायनरी कंपनियों ने जुलाई में पहले से ज्यादा कच्चे तेल को प्रोसेस किया है। 1.94 करोड़ टन के साथ जुलाई में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग पिछले साल के मुकाबले 9.6 प्रतिशत ज्यादा रही है। सरकारी तेल रिफायनरी ने 5.6 प्रतिशत ज्यादा यानि 1.1 करोड़ टन और निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल के मुकाबले 14.4 प्रतिशत ज्यादा कच्चा तेल प्रोसेस किया।

इंडियन ऑयल ने पाइपलाइन से ईंधन चोरी रोकने का ढूंढ निकाला नया तरीका, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लेगी मदद

नई दिल्ली। एजेंसी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देशभर में अपने पाइपलाइन नेटवर्क की निगरानी को ड्रोन की तैनाती कर रही है। कंपनी ने अपनी पाइपलाइनों से ईंधन की चोरी को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को दोगुना कर दिया है। इससे न केवल चोरी रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी पहली ही प्रौद्योगिकी और गश्त के जरिए अपनी 15,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क में किसी तरह के रिसाव की निगरानी करती है। अब कंपनी अपने नेटवर्क की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है।

अधिकारियों ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से 2020-21 में ईंधन चोरी के 34 मामलों को विफल किया गया और 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ताजा घटना 17 अगस्त को सोनीपत, हरियाणा में हुई। अधिकारी ने बताया कि पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (मार्ग का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 के तहत पाइपलाइन से किसी तरह की चोरी का प्रयास गंभीर अपराध है। यह गैर-जमानती अपराध है। इसमें दोषी को 10 साल या अधिक की सजा हो सकती है।

मथुरा-जालंधर पाइपलाइन की ड्रोन से निगरानी

आईओसी ने हाल में मथुरा-जालंधर पाइपलाइन के 120 किलोमीटर के दिल्ली-पानीपत खंड की ड्रोन के जरिए निगरानी शुरू की है। एक अधिकारी ने कहा कि इन पाइपलाइनों से काफी ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पादों मसलन पेट्रोल और डीजल का उच्च दबाव पर प्रवाह होता है। इनमें किसी तरह की चोरी के प्रयास से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं और जानमाल का नुकसान हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि आईओसी ने पाइपलाइन नेटवर्क

के प्रवाह की नजदीकी से निगरानी के लिए एससीएडीए-आधारित प्रणाली लगाई है। इसके अलावा कंपनी लीकेज को को पकड़ने वाली प्रणाली (एलडीएस) का भी इस्तेमाल कर रही है।

वॉलमार्ट के सीईओ ने भारतीय बाजार की जमकर तारीफ

2025 तक जताई यह संभावना

नई दिल्ली। एजेंसी

वॉलमार्ट इंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डग मैकमिलन का मानना है कि भारत दुनिया के सबसे रोमांचक खुदरा बाजारों में से है। उन्होंने कहा कि देश के खुदरा बाजार की अपनी विशिष्टता है और यह 2025 तक बढ़कर 1,000 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। कन्वर्जेंसॅवॉलमार्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैकमिलन ने बुधवार को कहा कि भारतीय बाजार की विविधता को देखते हुए कंपनी को 'स्थानीय स्तर पर सोचना होगा और स्थानीय स्तर पर ही क्रियान्वयन करना होगा। उन्होंने कहा, ''भारत इतना विविधता वाला बाजार है, कई मायनों में यह एक देश नहीं है। ऐसे में हमें स्थानीय सोचना होगा और स्थानीय का क्रियान्वयन करना होगा, जिसके अपने नियम होते हैं। ऐसे में हमें इन नियमों के अनुरूप चलना होगा।

मैकमिलन ने कहा कि अभी वॉलमार्ट को बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। ऐसे में कंपनी अलग तरीके से परिचालन कर रही है। वॉलमार्ट के शीर्ष कार्यकारी ने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका और चीन के साथ भारत उसके तीन प्रमुख बाजारों में से है। कन्वर्जेंसॅवॉलमार्ट कार्यक्रम वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम है। मैकमिलन ने कहा कि वॉलमार्ट की ई-कॉमर्स इकाई फ्लिपकार्ट और डिजिल भुगतान कंपनी फोनपे दोनों ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन कंपनियों के आंकड़े उत्साहजनक हैं। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट के मंच पर अब तीन लाख से अधिक मार्केटप्लेस विक्रेता हैं। वहीं फोनपे के प्रयोगकर्ताओं की संख्या 30 करोड़ से अधिक हो चुकी है। फ्लिपकार्ट भारतीय बाजार में अमेरिकी की ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है।

जल्द ही छह और प्राइवेट कंपनियां बेचेंगी पेट्रोल-डीजल

ईंधन बाजार पर अभी सरकारी कंपनियों का कब्जा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के ईंधन बाजार में छह और निजी कंपनियां दस्तक देने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इन कंपनियों को सरकार से पेट्रोल-डजील बेचने की अनुमति मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक, जिन कंपनियां को पेट्रोल-डीजल बेचने की अनुमति मिलने वाली है उनके नाम हैं आईएमसी , ऑनसाइट एनर्जी, असम गैस कंपनी, एमके एग्रोटेक, आरबीएमएल सॉल्यूशंस इंडिया, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन कंपनियों द्वारा प्रचालन शुरू करने के बाद ईंधन बाजार में कुल 14 कंपनियां काम करने लगेंगी।

उपभोक्तओं को फायदा होगा

इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2019 में संशोधित मार्केट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स नियमों के आधार पर निजी कंपनियों को ईंधन बाजार में कारोबार करने की अनुमति दी गई है। उम्मीद है कि इससे पेट्रोलियम रिटेल बिजनेस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्तओं को फायदा होगा। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, नए लाइसेंस उन कंपनियों को दिए गए थे, जिनकी न्यूनतम नेटवर्थ 250 करोड़ रुपये थी। साथ ही कंपनियों को 2000 करोड़ रुपये के निवेश से इसकी शुरुआत करनी होगी। साल 2019 के नियमों के मुताबिक लाइसेंस मिलने के 5 साल के अंदर कंपनियों को कम से कम 100 रिटेल आउटलेट्स तैयार करने होंगे, जिसमें से 5 फीसदी दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में होने चाहिए।

सरकारी कंपनियों का अभी बाजार पर कब्जा

ईंधन बाजार पर मौजूदा समय में देश की सरकारी कंपनियों का कब्जा है। देश में अभी 90 फीसी पेट्रोल पंप के कारोबार पर सरकार कंपनियों का कब्जा है, बाकी आरआईएल और नायरा इएर्जी और शेल के पास है। इन कंपनियों के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप के जरिये ईंधन की आपूर्ति संभव हो पाएगी।

देश में किस कंपनी के कितने पेट्रोल पंप

आईओसी	32,062
बीपीसीएल	18,637
एचपीसीएल	18,634
आरआईएल/आरबीएमएल	1,420
एनईएल	6,059
शेल	264
अन्य	18
कुल	77,094

कीमत तय करने को लेकर संशय

एक निजी कंपनी के अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने के शर्त पर बताया कि छह निजी कंपनियों की बाजार में एंट्री के साथ कुल 14 कंपनियां पेट्रोल-डीजल बेचना शुरू कर देंगी। हालांकि, अभी भी कीमत तय करने की रणनीति को लेकर निजी कंपनियों में संशय की स्थिति है। ऐसा इसलिए कि निजी कंपिनयों को 15 दिन के औसत के आधार पर कीमत अभी भी तय करनी होती है। इससे कंपनियों को कीमत निर्धारण करने में आगे भी परेशानी आएगी।

फेसबुक स्मॉल बिज़नेस एडवरटाइजर्स को लोन लेने में करेगा मदद

बिज़नेस लोन उपलब्ध करवाने के लिए लोन प्रोवाइडर पार्टनर इंडिफी के साथ करार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

फेसबुक इंडिया ने ऐसे स्मॉल और मीडियम बिज़नेस (एसएमबी) की मदद करने के लिए जो फेसबुक पर ऐड्वर्टाइज़मेंट करते हैं, एक नए कार्यक्रम, 'स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव' की घोषणा की, जहां इंडिपेंडेंट लोन देने वाले पार्टनर्स के माध्यम से फेसबुक उन्हें तुरन्त क्रेडिट उपलब्ध करा सकेगा। फेसबुक ने, इंडिफी, पहली इस तरह से क्रेडिट देने वाले पार्टनर, के साथ इस बाबत करार किया है और कार्यक्रम के माध्यम से भविष्य में और अधिक पार्टनर्स को बोर्ड में लाने की कोशिश है। इनिशिएटिव का उद्देश्य स्मॉल बिज़नेस के लिए बिज़नेस लोन को अधिक आसानी से उपलब्ध कराना और भारत के एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट अंतर को कम करना है। फेसबुक के लिए भारत पहला ऐसा देश है जहां यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत के 200 कस्बों और शहरों में रजिस्टर्ड बिज़नेस के लिए शुरू किया गया है।

फेसबुक इंडिया के वीपी और एमडी अजीत मोहन ने लॉन्च इवेंट में कहा, 'फेसबुक भारत के स्मॉल बिज़नेस के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। समय पर पूंजी उपलब्ध होना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें वसूली शुरू करने और ग्रोथ करने में मदद मिल सकती है। देश ने पिछले कुछ वर्षों में आसान लोन उपलब्धता बहुत तेजी से बढ़ी है। एक कंपनी के रूप में, हम डिजिटल बदलाव के कगार पर हैं और हमारा मानना है कि स्मॉल बिज़नेस लोन इनिशिएटिव नए उद्यमियों को उनके आइडिया और उनके जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकता है।'

'फेसबुक इंडिया द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ पार्टनरशिप में आयोजित कार्यक्रम – 'फाइनेंशियल इन्क्लूजन के माध्यम से एमएसएमई विकास को सक्षम करना' – की घोषणा एक वर्चुअल कार्यक्रम में हुई। इस कार्यक्रम में शामिल नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने मुख्य भाषण दिया। मुख्य भाषण के दौरान, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, 'हमारे इंडस्ट्रीज़ को, विशेष रूप से एमएसएमई को, जरूरी लिक्विडिटी, उपलब्ध कराने की आवश्यकता बढ़ रही है। फेसबुक द्वारा स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव जैसे नए क्रेडिट मॉडल अपनाने से भारत को एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है, जिससे उनके भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा, 'फिक्की और फेसबुक एमएसएमई क्षेत्र को सही अवसरों, स्किल्स और सोल्युशंस के साथ सशक्त बनाने की साझा दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। फिक्की ने भारत के एमएसएमईस के विकास के लिए निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी की हमेशा पक्ष लिया है, और इंडस्ट्री को अधिक आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए फेसबुक के स्मॉल बिज़नेस लोन पहल के शुभारंभ का स्वागत करता है। हम आने वाले महीनों में, एमएसएमई क्षेत्र को गति प्रदान करने वाले, ऐसे सोल्युशंस और कार्यक्रम लाने के लिए फेसबुक के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।'

सोना 177 रुपये टूटा, 47435 रुपये पर आ गया 10 ग्राम का भाव

एजेंसी

बुधवार को लगातार दूसरे दिन वायदा कारोबार में सोने के भाव में गिरावट दिखी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर गोल्ड वायदा भाव सुबह 177 रुपये टूटकर 47,435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। इससे पिछले ट्रेड में यह 47,612 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुधवार को सुबह 11.33 बजे के आसपास श्र्ंे पर सोना 47435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

अप्रैल-जून में कई गुना बढ़ा गोल्ड इंपोर्ट

सोने का आयात अप्रैल-जून 2021 तिमाही के दौरान कई गुना बढ़कर 7.9 अरब डॉलर (58,572.99 करोड़ रुपये) हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष कोराना वायरस के प्रकोप और सख्त लॉकडाउन के चलते इसी अवधि में सोने का आयात 68.8 करोड़ डॉलर (5,208.41 करोड़ रुपये) तक गिर गया था। अप्रैल-जून 2021 तिमाही में चांदी का आयात 93.7 प्रतिशत घटकर 3.94 करोड़ डॉलर रहा। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल-जून के दौरान सोने के आयात में इतनी वृद्धि से देश का व्यापार घाटा यानी आयात और निर्यात के बीच अंतर बढ़कर लगभग 31 अरब डॉलर हो गया है।

चांदी वायदा की कीमत

सोने की ही तरह चांदी वायदा में भी बुधवार को गिरावट का रुख है। एमसीएक्स पर सितंबर सिल्वर वायदा भाव 473 रुपये गिरकर 63,001 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला। इससे पिछले ट्रेड में शाम को चांदी वायदा का बंद भाव 63,474 रुपये प्रति किलोग्राम था। बुधवार सुबह 11.33 बजे के आसपास एमसीएक्स पर चांदी 63226 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी।

सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमत

रुपये के मूल्य में सुधार आने के बावजूद मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 170 रुपये की तेजी के साथ 46,544 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी 172 रुपये की तेजी के साथ 61,584 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 61,412 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,801 डॉलर प्रति औंस पर बोला गया। वहीं चांदी मामूली गिरावट के साथ 23.60 डॉलर प्रति औंस रह गई।

रिकॉर्ड हाई से कितना नीचे आया हाजिर भाव

सोने का हाजिर भाव इस वक्त इसके रिकॉर्ड हाई से 10,464 रुपये टूट चुका है। पिछले साल अगस्त में सोने की दिल्ली सर्राफा बाजार में कीमत 57008 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच सोने की कीमत में तेज उछाल दर्ज किया गया था। फिलहाल सोने में कभी तेजी और कभी गिरावट देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते सोना आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है। इस साल के आखिर तक ये 50 हजार रुपये तक जा सकता है।

पापड़ खरीद रहे हैं तो देना होगा GST

मुंबई। एजेंसी

कोई भी गुजराती थाली पापड़ के बिना पूरी नहीं होती, चाहे वह तला हुआ पापड़ हो या फिर भुना हुआ। लेकिन क्या पापड़ जीएसटी के दायरे में

आता है? इस सवाल का जवाब दिया है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) की गुजरात बेंच (Gujrat Bench) ने। एएआर गुजरात ने माना है कि पापड़ पर शून्य जीएसटी लगेगा। दिलचस्प बात यह है कि एएआर बेंच ने पाया कि पहले पापड़ हाथ से बनते थे। इसलिए उन्हें उन्हें गोल आकार देना आसान होता था। आज तकनीक की प्रगति के साथ, पुराने पारंपरिक गोल पापड़ के साथ-साथ विभिन्न आकारों और साइज के पापड़ उपलब्ध हैं। लेकिन जब तक विभिन्न तरह के पापड़ों की सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और उपयोग के संबंध में सामान एक जैसा है, ये सभी पापड़ एचएसएन 19059040 में वर्गीकृत एक ही पापड़ रहेंगे। वर्तमान में इस वर्गीकरण के लिए जीएसटी दर शून्य है।

ग्लोबल गृह उद्योग ने मांगा था स्पष्टीकरण

पापड़ों पर जीएसटी को लेकर स्पष्टीकरण ग्लोबल गृह उद्योग नामक मैन्युफैक्चरर की मांग पर आया है। मैन्युफैक्चरर ने अपने उत्पादों के वर्गीकरण पर एक निर्णय की मांग की थी। ग्लोबल गृह उद्योग पूरी पापड़ और अनफ्राइड पापड़ (जीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, चावल और मूंग दाल जैसी किस्मों में) का उत्पादन करता है। पापड़ एक भारतीय भोजन है जो मुख्य रूप से आटे, मसाले, नमक और तेल जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है। यह उत्पाद बिना तला हुआ है और यह पका हुआ भोजन नहीं है। इसके अलावा यह इंस्टेंट फूड नहीं है। आवेदक ने समझाया कि उपभोक्ताओं को पापड़ खाने के लिए पहले इसे भूनना या तलना पड़ता है।

फ्रायम्स पर 18 फीसदी जीएसटी

गौरतलब है कि कई महीने पहले सोनल प्रॉडक्ट्स के मामले में, गुजरात एएआर बेंच ने फ्रायम्स को पापड़ नहीं माना था और 18ज्ञ जीएसटी के अधीन रखा था। फ्रायम्स के लिए सामग्री में मैदा रहता है, जिसमें अन्य एडिटिव्स मिले रहते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है, 'अतीत में उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों ने फ्रायम्स को पापड़ माना है। यहां तक कि अगर हम केवल हाल के एएआर नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि चूंकि फ्रायम्स भी मसालों के साथ मिश्रित आटा होते हैं और विभिन्न आकारों में आते हैं, इसलिए इन्हें भी शून्य जीएसटी दर के अधीन पापड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।'

खरीदकर पी रहे हैं लस्सी तो नही लगेगा जीएसटी, फ्लेवर्ड मिल्क पर 12 प्रतिशत

मुंबई। एजेंसी

जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने माना है कि लस्सी माल और सेवा कर से मुक्त है। एएआर ने हाल के एक मामले में यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ, वर्गीकरण में जटिलताओं के कारण एएआर पीठों ने अतीत में माना है कि फ्लेवर्ड दूध को जीएसटी से छूट नहीं है। लस्सी वाले मामले में वलसाड स्थित निर्माता और आपूर्तिकर्ता संपूर्ण डेयरी एंड एग्रोटेक ने लस्सी पर लागू जीएसटी दर को लेकर एएआर-गुजरात से संपर्क किया था। वलसाड स्थित डेयरी 'एलन' ब्रांड नाम के तहत लस्सी बेचती है। बिक्री चार फ्लेवर्स में की जाती है- सादा (बिना चीनी या नमक के), जीरा के साथ नमकीन, चीनी के साथ मीठा स्ट्रॉबेरी, और चीनी के साथ मीठा ब्लूबेरी।

क्या कहा एएआर बेंच ने

एएआर बेंच ने कहा कि बनाकर बेची जा रही लस्सी की मुख्य सामग्री दही, पानी और मसाले हैं। बोतल पर प्रदर्शित सामग्री में पैश्चराइज्ड टोंड दूध, मसाले, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, नमक, एक्टिव कल्चर, प्राकृतिक जैसे एडेड फ्लेवर और स्टेबलाइजर शामिल थे। बोतल ने प्रदर्शित किया कि यह एक 'डेयरी-बेस्ड फरमेंटेड ड्रिंक' है। सौभाग्य से निर्माता और अंतिम उपभोक्ता के लिए दही, लस्सी और छाछ एक विशिष्ट वर्गीकरण (HSN 040390) के अंतर्गत आते हैं और GST से मुक्त हैं। कर विशेषज्ञ बताते हैं कि फ्लेवर्ड दूध के निर्माता और आपूर्तिकर्ता उतने भाग्यशाली नहीं हैं।

फ्लेवर्ड दूध पर 12 फीसदी जीएसटी

गुजरात एएआर ने ही अमूल के मामले में, जो फ्लेवर्ड दूध का निर्माण और आपूर्ति करता है, माना था कि फ्लेवर्ड दूध पर 12% की जीएसटी दर लागू होगी (HSN 22029930)। फ्लेवर्ड मिल्क, दूध में चीनी और अनुमत फ्लेवर को मिलाकर तैयार होता है। एक कर विशेषज्ञ का कहना है, 'संक्षेप में, लस्सी और फ्लेवर्ड दूध दोनों ही डेयरी आधारित पेय हैं, लेकिन वर्गीकरण कोड उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं।'

यस बैंक और व्हीगल्सा ईएमआई के बीच टू-व्हीहलर लोन्स के लिए को-लेंडिंग करार

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

येस बैंक और व्हीसल्सा ईएमआई प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिस्पर्द्धी ब्याहज दरों पर दोपहिया वाहनों के लिए ऋण उपलब्ध् कराने हेतु आपस में महत्वंपूर्ण को-लेंडिंग करार किया है। इस साझेदारी का उद्देश्यन अपनी-अपनी क्षमताओं को उपयोग में लाते हुए पूरे भारत में दोपहिया वाहन खरीदारों को निर्बाध ऋण अनुभव प्रदान करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सह-उधार ढांचा एक सहयोग उपकरण प्रदान करता है जो बैंक की कम लागत वाली निधियों और एनबीएफसी की सोर्सिंग एवं सर्विसिंग विशेषज्ञता से लाभान्वित होता है। यह गठबंधन दोनों उधारदाताओं की ताकत का लाभ उठायेगा और इससे सभी शेयरधारकों का हित होगा और इस प्रकार, कम सेवा वाले बाजारों तक इसकी पहुंच का विस्तार होगा।

व्हील्सईएमआई, टू-व्हीलर ओनरशिप-राइडरशिप लाइफसाइकिल के साथ किफायती समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जो कामकाजी परिवारों के लिए किफायती है। इनमें नए और पुराने दोपहिया वाहनों का वित्तपोषण, इलेक्ट्रिक बाइक तक पहुंच, बीमा, सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स प्रबंधन और पुराने दोपहिया वाहनों के लिए एक पारदर्शी बाजार शामिल हैं। व्हील्सईएमआई अपने अनूठे मॉडल के माध्यम से गहरे भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों को वित्तपोषित करने में माहिर है, जो ग्राहकों के कम प्रतिनिधित्व वाले सेगमेंट में गतिशीलता को सक्षम करते हुए शहरी और ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्रों के बीच डिजिटल खाई को पाटता है। इस व्यवस्था के तहत, दोनों ऋणदाताओं ने पहले चरण में 1 लाख से अधिक दोपहिया वाहनों को वित्तपोषित करने की योजना बनाई है।

यस बैंक के रिटेल बैंकिंग के ग्लोबल हेड राजन पेंटल ने कहा, 'हम व्हील्सईएमआई के साथ साझेदारी करके खुश हैं। यह व्यवस्था बैंक को नए बाजारों में प्रवेश करने और अपनी उपस्थिति को गहरा करने के द्वारा अपनी पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। हम अर्धशहरी और ग्रामीण बाजारों में व्हील्स ईएमआई की ताकत का लाभ उठाने और इस साझेदारी के माध्यम से एक लाभदायक और टिकाऊ दोपहिया ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए तत्पर हैं।'

श्रीनिवास कांथेती, एमडी और सीईओ, व्हील्सईएमआई ने कहा, 'दोपहिया वाहनों में भारी व्हाइट स्पेनस है, और हम यस बैंक के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं। यह साझेदारी हमारे निवेश का लाभ उठाएगी, बैंक के लिए एक गुणवत्तापूर्ण पुस्तक का निर्माण करते हुए हमारी पहुंच को बढ़ाएगी।'

रेस्टोरेंट-टेक स्टार्टअप 'पेटपूजा'

भारत भर में 25,000 से अधिक रेस्टोरेंट को बेहतर संचालन में कर रहा मदद

'पेटपूजा' का पॉइंट-ऑफ-सेल सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट प्रबंधन स्टार्टअप

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

कोविड-19 महामारी ने पूरे भारत में विभिन्न व्यवसाय के साथ रेस्टोरेंट उद्योग में भी बड़ी क्षति पहुंचाई है। ऐसे में अहमदाबाद स्थित रेस्टोरेंट-टेक स्टार्टअप 'पेटपूजा' रेस्टोरेंट के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। अपने उन्नत तकनीकी उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके 'पेटपूजा' रेस्टोरेंट संचालकों को उनके कारोबार को फिर से पटरी पर लाने में मदद कर रही है। साथ ही ऐसे विकट एवं परीक्षण समय में उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए व्यवसाय विकास को प्रोत्साहन दे रही है। 'पेटपूजा' के अभिनव समाधान छोटे पैमाने के रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, स्वतंत्र आउटलेट और बहुत कुछ सहित सभी रेस्टोरेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसंगत रूप से डिजाइन किए गए हैं। हाल में भारत भर में 25,000 से अधिक ईं आउटलेट्स को सशक्त बनाने वाले उनके ग्राहकों में फाइन-डाइन्स, क्यूएसआरएस, क्लाउड किचन, फूड कोर्ट, कैफे, बार और बेकरी जैसे सभी प्रारूपों के बड़े नाम शामिल हैं।

'पेटपूजा' के सह-संस्थापक पार्थिव पटेल ने कहा कि, तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण रेस्टोरेंट उद्योग एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कोविड -19 महामारी ने इस परिवर्तन की गति को काफी तेज कर दिया है। इसके अलावा, खाने की आदतों में बदलाव के परिणामस्वरूप फूड एग्रीगेटर्स (खाद्य समूहक) से डिलीवरी ऑर्डर में वृद्धि हुई है और रेस्टोरेंट के लिए मार्जिन कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में, रेस्टोरेंट के पास अपनी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए अधिक कुशल बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 'पेटपूजा' का पॉइंट-ऑफ-सेल सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट प्रबंधन के सभी मुख्य कार्य जैसे कि बिलिंग, ऑर्डर लेना, किचन ऑर्डर टिकट, इन्वेंट्री और स्टॉक प्रबंधन, मेनू अपडेशन, ऑनलाइन डिलीवरी आदि को नियंत्रित करता है। इस प्रकार यह अतिरिक्त मानव हस्तक्षेप के बिना सुचारू और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करता है।

'पेटपूजा' एक रेस्टोरेंट के लिए बाहरी प्रक्रियाओं को भी स्वचालित करता है,, जैसे कि जोमेटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के माध्यम से प्राप्त डिलीवरी ऑर्डर को प्रबंधित करना या कई भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत करना। कुल मिलाकर, कोर इ्ध्य मॉड्यूल 80इ थर्ड पार्टी सर्विस के साथ एकीकृत होता है, जिससे रेस्टोरेंट एक ही डैशबोर्ड से सब कुछ प्रबंधित कर सकते हैं। पेटपूजा के सह-संस्थापक अपूर्व पटेल ने कहा कि, हम अपने रेस्टोरेंट भागीदारों के लिए प्रति दिन 10 लाख से अधिक ऑर्डर संसाधित करते हैं और जोमैटो और स्विगी के ऑर्डर वॉल्यूम में 20इ से अधिक का योगदान देते हैं। पेटपूजा के रेस्टोरेंट प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रेस्टोरेंट अपने खर्च का प्रबंधन भी कर सकते हैं। यह रेस्टोरेंट को उनकी बिक्री, लाभ, व्यय, जीएसटी रिपोर्टिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला संचालन और ग्राहक डेटा को ट्रैक और तुलना करने में मदद करने के लिए गहन रिपोर्ट और विश्लेषण प्रदान करता है।

क्लाउड-आधारित तकनीक होने के नाते यह सॉफ्टवेयर कच्चे माल के ऑर्डर से लेकर ग्राहक को बिलिंग करने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने तक सभी कार्यों की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम बनाता है। यह उपकरण वास्तव में एक रेस्टोरेंट को ऑटो-पायलट पर चलाने की अनुमति देता हैं, जो कि मालिकों और प्रबंधकों को परिचालन संबंधी चिंताओं से मुक्त करता हैं और उन्हें भोजन और ग्राहकों के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम बनाता है। पेटपूजा रेस्टोरेंट संचालन को और अधिक अनुकूलित करने के लिए स्मार्ट तकनीकी उत्पादों को पेश करने का प्रयास करता रहता है।यह जल्द ही बाजार में वॉयस-आधारित सेल्फ-ऑर्डरिंग कियोस्क, एक वेटर कॉलिंग सिस्टम, कुछ और नवीन सुविधाओं और नए उत्पादों को लॉन्च करने के लिए तैयार है।

महामारी के बीच लोगों को पड़ी 'ऑनलाइन रहने की आदत' : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोविड-19 महामारी के कारण 'डिजिटल' कार्य न केवल रोजमर्रा की जिंदगी का अहम् हिस्सा बन गया बल्कि कई लोगों को इस दौरान 'ऑनलाइन रहने की आदत' सी बन गई। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। साइबर सिक्युरिटी कंपनी नोर्टनलाइफलॉक ने उपभोक्ताओं के घर पर रहते हुए ऑनलाइन व्यवहार की समीक्षा के लिए एक नया वैश्विक अध्ययन किया है। अध्ययन के भारतीय खंड से मिले निष्कर्षों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल हर तीन में से दो भारतीय (66 प्रतिशत) ने कहा कि वे महामारी की वजह से ऑनलाइन रहने की आदत के शिकार हो गये हैं।

द हैरिस पोल द्वारा किए गए इस ऑनलाइन अध्ययन में 1,000 से ज्यादा भारतीय वयस्कों ने हिस्सा लिया। उनमें से हर 10 में से आठ (82 प्रतिशत) लोगों ने कहा कि शिक्षा और पेशेवर कार्य के लिए इस्तेमाल के इतर डिजिटल स्क्रीन के सामने बीतने वाला उनका समय महामारी के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गया।

औसतन भारत में एक वयस्क पेशेवर काम या शिक्षा कार्यों से इतर स्क्रीन के सामने हर दिन 4.4 घंटे गुजारता है। सर्वेक्षण में शामिल भारतीयों ने कहा कि स्मार्ट फोन वह आम उपकरण है जिसके इस्तेमाल में वह काफी ज्यादा समय (84 प्रतिशत) गुजारते हैं।

अध्ययन में शामिल अधिकांश भारतीयों (74 प्रतिशत) ने माना कि वे स्क्रीन के सामने जितना समय बिताते हैं उससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि आधे से अधिक (55 प्रतिशत) ने कहा कि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लगभग 76 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे दोस्तों के साथ समय बिताने जैसी गतिविधियों में शामिल होकर स्क्रीन के सामने बिताने वाले अपने समय को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

नॉर्टनलाइफलॉक में भारत और सार्क देशों के बिक्री एवं क्षेत्र विपणन निदेशक रितेश चोपड़ा ने कहा, 'यह समझ में आता है कि महामारी ने उन गतिविधियों के लिए स्क्रीन पर हमारी निर्भरता बढ़ा दी है जो अन्यथा ऑफलाइन की जा सकती थीं। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए अपने ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन समय के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है ताकि उनके स्वास्थ्य और, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।'

उन्होंने साथ ही कहा कि ऑनलाइन परिदृश्य में साइबर खतरों की संख्या और प्रकारों में वृद्धि हुई है। चोपड़ा ने कहा, 'उपयोगकर्ताओं को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने कनेक्टेट उपकरणों का उपयोग कैसे और कहां करते हैं। सुविधा सुरक्षा से बढ़कर नहीं होनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी के नुकसान के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं और माता-पिता के लिए इस बात को जानना तथा अपने बच्चों को साइबर सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।

अब तक रिकॉर्ड 873.68 लाख टन धान की खरीद

केंद्र ने 1.65 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्र ने सितंबर में समाप्त होने वाले विपणन वर्ष 2020-21 में अब तक रिकॉर्ड 873.68 लाख टन धान की खरीद की है, जिसके लिए करीब 1.65 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, ''खरीफ विपणन सत्र 2019-20 में खरीद के उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए धान खरीद अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। लगभग 129.03 लाख किसान मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुई खरीद से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 1,64,951.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।'' विज्ञप्ति में कहा गया कि चालू खरीफ सत्र 2020-21 में धान की खरीद, इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। इसमें आगे कहा गया, ''23 अगस्त 2021 तक 873.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है (इसमें खरीफ फसल का 707.69 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 165.99 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 763.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।'' विज्ञप्ति के मुताबिक गेहूं की खरीद का काम वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 में इसकी खरीद वाले राज्यों में पूरा हो चुका है और 18 अगस्त 2021 तक 433.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली गई है। बयान में कहा गया है, ''मौजूदा रबी विपणन सत्र के दौरान 49.20 लाख किसानों को खरीदा का लाभ मिला है। इस दौरान किसानों को 85,603.57 करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया।''

केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का वैल्यू फंड एनएफओ 27 अगस्त तक

वैल्यू फंड 6 सितंबर, 2021 से चल रहे निवेश के लिए फिर से खुला

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना नया फंड ऑफर (एनएफओ) लॉन्च करने की घोषणा की है। केनरा रोबेको वैल्यू फंड - एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना जो एक मूल्य निवेश रणनीति का पालन करेगी। उन व्यवसायों में निवेश करने के लिए जो अपने आंतरिक मूल्यों से कम कीमत पर व्यापार कर रहे हैं और भविष्य में उनके वास्तविक मूल्य का एहसास होने की उम्मीद है। केनरा रोबेको वैल्यू फंड एनएफओ 13 अगस्त 2021 से खुल कर 27 अगस्त 2021 को बंद होगा। नई योजना 6 सितंबर, 2021 से चल रहे निवेश के लिए फिर से खुल रही है। एनएफओ में न्यूनतम निवेश राशि ₹ 5,000 होगी और उसके बाद लंपसम निवेशकों के लिए ₹ 1.00 के गुणक और मासिक एसआईपी ₹ 1,000 और उसके बाद ₹ 1.00 के गुणक में होंगे। एसएंडपी बीएसई 500 टीआरआई केनरा रोबेको वैल्यू फंड के लिए बेंचमार्क होगा।

केनरा रोबेको वैल्यू फंड तब पोर्टफोलियो के लिए परिभाषित अवसर आकार और जोखिम सीमा को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो का निर्माण करेगा। पोर्टफोलियो निर्माण प्रक्रिया को विभिन्न इन-हाउस क्वांट मॉडल द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य उन व्यवसायों में निवेश करना है जिनमें मजबूत बुनियादी बातों के कारण अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता मौजूद है। केनरा रोबेको वैल्यू फंड इक्विटी में महत्वपूर्ण निवेश करेगा और इसका लक्ष्य भारतीय बाजारों में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है, जिसमें कम मूल्यांकन वाली कंपनियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

केनरा रोबेको वैल्यू फंड एनएफओ को लॉन्च करने के औचित्य पर बोलते हुए, सेल्स एंड मार्केटिंग के हेड श्री मोहित भाटिया ने कहा, 'हम अपनी नई पेशकश केनरा रोबेको वैल्यू फंड को ऐसे समय में पेश करते हुए खुश हैं, जब बाजार वैश्विक और घरेलू तरलता (लिक्विडिटी) से प्रेरित हो रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक समय के साथ साबित हो चुकी निवेश रणनीति है जो अपने आंतरिक मूल्य से नीचे व्यापार करने वाले व्यवसायों के पोर्टफोलियो की पहचान करके और इन कंपनियों / व्यवसायों में निवेश करके दीर्घकालिक धन बनाने का प्रयास करती है, जो सुरक्षा के उच्च मार्जिन की पेशकश करते हैं। एक आकर्षक अपसाइड पोटेंशिअल के साथ एक फायदेमंद इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हुए फंड इन गलत कीमत के अवसरों से लाभ उठाने का प्रयास करेगा। श्री भाटिया ने आगे कहा, 'केनरा रोबेको वैल्यू फंड उन अंडरवैल्यूड शेयरों में निवेश करेगा जो सुरक्षा का उचित मार्जिन प्रदान करते हैं, जिससे नकारात्मक जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।' श्री निमेश चंदन – प्रमुख – निवेश , इक्विटी ने कहा, 'ज्यादातर समय, जब मैं निवेशकों से मूल्य निवेश के बारे में बात करता हूं, तब भी वे कम कीमत वाली कंपनी या कमाई के अनुपात की कीमत के साथ एक कंपनी खरीदते हैं। या वे अच्छी लाभांश उपज की तलाश में हैं। जबकि ये किसी कंपनी के सापेक्ष मूल्य का आकलन करने के लिए शॉर्ट-कट हैं, मूल्य निवेश इन मापदंडों पर सबसे सस्ती कंपनियों को खरीदने के बारे में नहीं है। मूल्य निवेश एक व्यापक दर्शन है जिसमें कंपनी को उसके आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर खरीदना शामिल है।श्री विशाल मिश्रा, फंड मैनेजर – इक्विटी, नई योजना केनरा रोबेको वैल्यू फंड का प्रबंधन करेंगे। श्री मिश्रा वर्तमान में केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, केनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर और केनरा रोबेको ब्लूचिप इक्विटी फंड के सह-निधि प्रबंधक भी हैं। एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक, श्री मिश्रा मई 2021 में केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड में शामिल हुए।

इन्फोसिस की बड़ी उपलब्धि

100 अरब डॉलर का मार्केट कैप छूने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनी

बेंगलुरु। एजेंसी

इन्फोसिस 100 अरब डॉलर या उससे अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली भारतीय कंपनियों में शामिल हो गई है। इस एमकैप वाले क्लब में अभी तक केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज , टीसीएस और एचडीएफसी बैंक थीं। इन तीनों कंपनियों का मार्केट कैप क्रमशः 186 अरब डॉलर, 180 अरब डॉलर और 116 अरब डॉलर है। मंगलवार को सुबह के कारोबार में इन्फोसिस ने यह उपलब्धि हासिल की, जब बीएसई पर इन्फोसिस के शेयर ने 1,755 रुपये का एक साल का उच्च स्तर छुआ। इससे कंपनी का एमकैप 100.7 अरब डॉलर हो गया। शेयर 1% की गिरावट के साथ 1,720 रुपये पर बंद हुआ। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी सुबह के कारोबार में इन्फोसिस का एम-कैप 100 अरब डॉलर के करीब था।

50 अरब डॉलर एमकैप पर पहुंचने में लग गए थे 20 साल

इन्फोसिस को 50 अरब डॉलर के मार्केट कैप तक पहुंचने में 20 साल लगे, वहीं अगले 50 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचने में एक साल से थोड़ा ही अधिक समय लगा। कंपनी ने सीईओ सलिल पारेख (Salil Parekh)

की अगुवाई में एक आश्चर्यजनक विकास दर हासिल की है। क्लाउड के माध्यम से डिजिटल ट्रान्सफॉरमेशन की अपने ग्राहकों की इच्छा और डेटा व एनालिटिक्स पर अधिक ध्यान देने के कारण आईटी कंपनियां महामारी से स्मार्ट रिकवरी दर्ज कर रही हैं। इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई (TV Mohandas Pai) का कहना है, '1994 में इन्फोसिस की वैल्युएशन 10 करोड़ डॉलर थी। 27 वर्षों में यह 100 अरब डॉलर को पार कर गई है और यह एक अच्छी कहानी है। इन्फोसिस का उदय, उदारीकरण और वैश्विक आईटी सेवा उद्योग के उदय के बाद के भारत के उदय को दर्शाता है।'

भारत में कॉर्पोरेट-गवर्नेंस के स्तर को उच्च बनाया

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चार्ल्स ई मेरिल प्रोफेसर मार्टी जी सुब्रह्मण्यम 1998 से 2011 तक इन्फोसिस के बोर्ड में थे। वह याद करते हैं कि जब वह कंपनी में शामिल हुए थे, इसका रेवेन्यु 4.7 करोड़ डॉलर था और 1500 कर्मचारी थे। आगे कहते हैं, 'इन्फोसिस ने भारत में कॉर्पोरेट-गवर्नेंस नैतिकता के लिए स्टैंडर्ड को ऊंचा किया। बोर्ड केवल देखने के लिए एक अलंकरण नहीं था। मेरे विचारों का सम्मान किया गया और प्रबंधन के साथ मेरी कई तीखी बहस हुईं। इन्फोसिस का सीक्रेट सुशासन, मूल्य और नैतिकता, कड़ी मेहनत और एनआरएन कार विजन है।'

1981 में हुई थी शुरू

इन्फोसिस बेंगलुरु स्थित कंपनी है। इसे एनआर नारायण मूर्ति ने 1981 में छह अन्य लोगों के साथ मिलकर शुरू किया था। इसे 1993 में भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया और यह 1999 में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय रजिस्टर्ड कंपनी बनी। इन्फोसिस को लंबे समय से भारतीय कॉरपोरेट्स के बीच कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है।

CCEA ने Anchorage के 15,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के Anchorage Infrastructure Investment के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। यह कंपनी कनाडा स्थित पेंशन फंड की सब्सिडियरी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने खास तौर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेक्टर में निवेश वाले इस एफडीआई प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। ये ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर के साथ-साथ एयरपोर्ट और एविएशन से जुड़े बिजनेस में निवेश से संबंधित हो सकता है। एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि इन निवेश प्रस्तावों में बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के शेयर को Anchorage को ट्रांसफर किए जाने और Anchorage Infrastructure Investment Holding Ltd में 2726247 Ontariao Inc द्वारा 950 करोड़ रुपये के निवेश भी शामिल हैं। 2726247 Ontariao Inc, OAC की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। यह OMERS की एडमिनिस्ट्रेटर है। यह कनाडा के सबसे बड़े डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान्स में से एक है। यह निवेश इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर (Infrastructure Sector) के साथ-साथ एयरपोर्ट सेक्टर के लिए भी बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। इस बयान में कहा गया है कि इस निवेश से देश में प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए विश्वस्तरीय एयरपोर्ट्स एवं ट्रांसपोर्ट से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास को काफी अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस बयान में कहा गया है कि इस निवेश से हाल में घोषित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) को भी काफी अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस पाइपलाइन के जरिए सरकार रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पावर ट्रांसमिशन लाइन और गैस पाइपलाइन जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट कंपनियों को मोनेटाइज करेगी। बयान में कहा गया है कि Anchorage Infrastructure Investment Holding Ltd कुछ सेक्टर्स में निवेश को इच्छुक है, जो NMP के अंतर्गत आते हैं।

तालिबान को कंगाल करने का प्लान, अमेरिका और आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने लिया बड़ा एक्शन, रोका काम

वॉशिंगटन। एजेंसी

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। अभी तक अधिकतर देशों ने तालिबानी शासन को मंजूरी नहीं दी है और इस बीच अब विश्व बैंक ने भी बड़ी कार्रवाई की है। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के हालात, खासतौर पर महिला अधिकारों की स्थिति से चिंतित होकर यह फैसला लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने सभी आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है और अब स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बता दें कि अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देगी लेकिन इससे करीब 2 हफ्ते पहले ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। इससे पहले अमेरिका ने भी बीते हफ्ते यह ऐलान किया था कि वह अपने देश में मौजूद अफगानिस्तान के सोने और मुद्राभंडार को तालिबान के कब्जे में नहीं जाने देगा। अकेले अमेरिका में ही अफगानिस्तान की करीब 706 अरब रुपये की संपत्ति है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी अफगानिस्तान की आर्थिक मदद रोक दी थी। आईएमएफ ने तालिबान के अफगानिस्तान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 460 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी 46 करोड़ डॉलर (3416.43 करोड़ रुपये) के आपातकालीन रिजर्व तक अफगानिस्तान की पहुंच को ब्लॉक करने की घोषणा की थी, क्योंकि देश पर तालिबान के नियंत्रण ने अफगानिस्तान के भविष्य के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है। विश्व बैंक के मौजूदा समय में अफगानिस्तान के अंदर दो दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।

जन्माष्टमी विशेष

नारियों के लिए शाश्वत आदर्श है श्रीकृष्ण का उदात्त चरित्र

पुराणों के अनुसार द्वापर युग में अवतरित हुए भगवान श्रीकृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए। इसके साथ ही समाज के हर वर्ग और विशेष रूप से नारी के सम्मान, गरिमा और अस्मिता को बनाए रखने के लिए अपने चरित्र के माध्यम से जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो पूरे समाज को प्रेरित करते हैं। यही वजह है कि महिलाएं आज भी श्रीकृष्ण में आदर्श पुरुष की छवि देखती हैं।

पर्व-निहितार्थ

डॉ. अलका जैन 'आराधना'

भारतीय संस्कृति-परंपराओं में कई पर्व सदियों से मनाए जा रहे हैं। इन पर्वों को मनाने का भले ही एक उद्देश्य जीवन में उल्लास-उमंग को सम्मिलित करना होता है लेकिन कई पर्व ऐसे हैं, जो उच्च सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने की प्रेरणा भी हमें देते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी ऐसा ही पर्व है। कृष्ण भक्तों के बीच इसका धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन यह पर्व पूरे समाज के समक्ष आदर्श जीवन-मूल्यों की महत्ता को भी रेखांकित करता है। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए यह पर्व मायने रखता है। दरअसल, युगों पहले श्रीकृष्ण ने अपने चरित्र और लीलाओं के माध्यम से समाज को स्त्री गरिमा और अस्मिता के रक्षण का जो संदेश दिया, उसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। ऐसे में श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के साथ ही हमें उनके चरित्र में निहित उदात्त मूल्यों को भी स्मरण रखना चाहिए।

नारी गरिमा को दिया महत्व

श्रीकृष्ण ना केवल स्वयं नारी गरिमा के महत्व को समझते थे, समाज में उस गरिमा को बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व कदम भी उठाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण की रानियों की संख्या सोलह हजार एक सौ आठ थी। भागवत पुराण के अनुसार सोलह हजार एक सौ स्त्रियां वास्तव में अलग-अलग राज्यों की राजकुमारियां थीं, जिन्हें नरकासुर नाम के राक्षस ने विवाह के उद्देश्य से बंदी बना रखा था। श्रीकृष्ण ने नरकासुर को परास्त कर इन राजकुमारियों को मुक्त करवाया। लेकिन एक असुर के महल में लंबे समय तक रहने के कारण समाज में कोई भी उन्हें अपनाने को तैयार नहीं हुआ और ना ही कोई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहता था। ऐसी विषम परिस्थिति में नारी सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए श्रीकृष्ण ने उन सोलह हजार एक सौ रानियों को अपनाकर उनसे विवाह किया और उनके लिए बहुत विशाल महल का निर्माण करवाया, जिसमें वो सुख-शांति से रह सकें। पुराणों के अनुसार श्रीकृष्ण का इन राजकुमारियों से विवाह सिर्फ प्रतीकात्मक था ताकि वे स्त्रियां समाज में पूरी गरिमा और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें।

स्त्री अस्मिता के रक्षक

श्रीकृष्ण के चरित्र की एक विशेषता यह भी है कि वे नारी अस्मिता की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी चीरहरण के समय जब उनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी, उनके महारथी पति, अनेक वीर पुरुष सिर झुकाए बैठे स्त्री अस्मिता के विध्वंस का यह दृश्य देखते रहे तो ऐसे में श्रीकृष्ण रक्षक बनकर प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को अनंत लंबाई प्रदान की। नारी अस्मिता की रक्षा का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण विश्व साहित्य में नहीं दिखता है। आज के दौर में जब घर-बाहर स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, अन्याय हो रहा है, तो ऐसे में श्रीकृष्ण की वो अद्वितीय पहल, हर पुरुष को आगे बढ़कर महिला अस्मिता की रक्षा को प्रेरित करती है।

नहीं माना किसी स्त्री को कमतर

श्रीकृष्ण को जन्म देवकी ने दिया पर उनका लालन-पालन यशोदा ने किया। लेकिन कृष्ण ने अपनी दोनों माताओं को पूरा सम्मान दिया। कृष्ण ने संसार के सामने यह आदर्श प्रस्तुत किया है कि सिर्फ जन्म देने वाली मां ही नहीं, पाल-पोसकर बड़ा करने वाली मां का दर्जा भी बहुत ऊंचा होता है। यानी, इसके माध्यम से उन्होंने यह मूल्य स्थापित करने का प्रयास किया कि मां के समतुल्य सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए।

इसी तरह हम सब जानते हैं कि श्रीकृष्ण की सबसे प्रिय सखी राधा थीं लेकिन इसके बावजूद वे सभी गोपियों से समान प्रेम करते थे, उनके मान और इच्छाओं का ध्यान रखते थे। इसके माध्यम से वह यह संदेश देते हैं कि किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। पुरुष प्रधान मानसिकता से इतर कृष्ण प्रेम संबंध में भी स्त्री-पुरुष को समतुल्य मानने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के पुरुष प्रधान समाज में जब महिलाएं अपने लिए पर्याप्त सम्मान और समान अधिकार चाहती हैं, तो श्रीकृष्ण का चरित्र सबसे उत्तम उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है।

नारी स्वतंत्रता के पक्षधर

आज के दौर में स्त्रियां अपनी अलग पहचान के साथ ही स्वतंत्रता और सम्मान भी चाहती हैं। वैसा ही सम्मान, जैसा श्रीकृष्ण अपने समकालीन स्त्रियों को देते थे। श्रीकृष्ण के चरित्र में, संपर्क में रहने वाली हर स्त्री की हर इच्छा को पूर्ण करने की अभिलाषा और चेष्टा दिखाई देती है। वे स्त्री मन की छोटी से छोटी बात को भी अनुभूति के धरातल पर समझते हैं। कृष्ण की समतामूलक दृष्टि में नर-नारी सब समान हैं। नर-नारी साथ मिलकर सभी त्यौहार मनाएं, यह पर्व-परंपरा, श्रीकृष्ण ने ही आरंभ की। उन्होंने स्त्रियों को घर की चाहरदीवारी से बाहर निकल जीवन को उल्लास से जीने को प्रोत्साहित किया। इसके जरिए उन्होंने यह सामाजिक मूल्य स्थापित किया कि स्त्री, पुरुष की दासी नहीं सहचरी है, सहधर्मिणी है। इस तरह श्रीकृष्ण का संपूर्ण चरित्र स्त्री-सशक्तिकरण के प्रणेता के रूप में आज हम सबके लिए अनुकरणीय है।

श्री कृष्ण के शरीर के 5 चमत्कारिक रहस्य

श्रीकृष्ण का जन्म एक रहस्य है। कहते हैं कि वे गर्भ से नहीं जन्में थे। श्री हरि विष्णु ने माता देवकी के पास बाल रूप में जन्म लिया था। हालांकि यह भी एक रहस्य ही है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे योग के हर अंग में पारंगत थे। योग के चलते ही उनका शरीर अद्भुत हो चला था। आओ जानते हैं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर उनके शरीर की 5 चमत्कारिक विशेषता।

1. भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघश्यामल था, काला या सांवला नहीं। इसीलिए उनका एक नाम श्याम है।
2. भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। जिसे युद्ध काल में छुपाने का वे हर समय प्रयत्न करते रहते थे।
3. भगवान् श्री कृष्ण के परमधामगमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थीं। वे जवान ही थे। 119 वर्ष की उम्र में वे अपने धाम चले गए थे।
4. भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जातीं थीं, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था।
5. भगवान श्रीकृष्ण के केश घुंघराले थे और उनकी आंखों बड़ी-बड़ी मोहक थी। आम लोगों की अपेक्षा यह केश और आंखें बहुत ही अलग थी।

तन पर पीले वस्त्र और सिर पर मोर मुकुट धारण किए, गले में बैजयंती माला और हाथों में बांसुरी लिए उनका रूप मनोरम नजर आता है। उपरोक्त बातें जैसा कि पुराणों में उनके रूप और रंग का वर्णन मिलता है उसके आधार पर है।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2021 : जानिए शुभ संयोग, पूजा मुहूर्त और पारण का समय

भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी या श्रीकृष्ण जयंती मनाई जाती है। श्रीकृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 30 अगस्त, दिन सोमवार को है। जानिए जन्माष्टमी के शुभ संयोग, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय-

जन्माष्टमी के दिन शुभ संयोग- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह 07 बजकर 47 मिनट के बाद हर्षण योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में हर्षण योग को बेहद शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। जन्माष्टमी के दिन कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र रहेगा।

अष्टमी तिथि- हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 29 अगस्त दिन रविवार को रात 11 बजकर 25 मिनट से शुरू होगी, जो 30 अगस्त को देर रात 1 बजकर 59 मिनट पर समाप्त होगी। कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था और व्रत उदया तिथि में रखना उत्तम माना जाता है। इसलिए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा।

जन्माष्टमी 2021 पूजा मुहूर्त- इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पूजा मुहूर्त 30 अगस्त की रात 11 बजकर 59 मिनट से देर रात 12 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। बाल गोपाल के पूजा की कुल अवधि 45 मिनट है।

व्रत पारण का समय- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण का समय 31 अगस्त को सुबह 09 बजकर 44 मिनट के बाद ही कर सकते हैं। इस समय ही रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा।

महामारी ने एशिया-प्रशांत में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेला: ADB

नई दिल्ली। एजेंसी

एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, कोविड महामारी ने 2020 में विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अनुमानित 7.5 से 8 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एडीबी ने चेतावनी दी है कि महामारी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ने के रास्ते में बडा खतरा है।

गरीबी रेखा के करीब रहने वालों की मुश्किलें बढ़ीं

एक 'की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की शुरूआत में दुनिया को तबाह करने वाली महामारी ने 'गरीबी रेखा से नीचे या उसके करीब रहने वाले लाखों लोगों के लिये मुश्किलों को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव लगातार सामने आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'जो लोग पहले से ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके गरीबी के दलदल में और फंसने का खतरा बन गया है।' यह मानते हुए कि महामारी ने समाज के बीच असमानता बढ़ा दी है, रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक गरीबी में बढ़त अनुमान से और भी अधिक हो सकती है।

महामारी का गरीबी खत्म करने के अभियान पर असर

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 20 करोड़ लोग या विकासशील एशिया की 5.2 प्रतिशत आबादी, 2017 तक अत्यधिक गरीबी में रहती थी। अगर कोविड महामारी न आई होती तो साल 2020 तक गरीबी में फंसे लोगों की संख्या 2.6 प्रतिशत तक गिर गयी होती। एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवादा ने एक बयान कहा कि 2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए, सरकारों को उच्च गुणवत्ता और समय पर डेटा का उपयोग कार्रवाई के लिए एक गाइड के रूप में करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिकवरी की स्थिति में गरीब और कमजोरों को भी मुश्किलों से बाहर निकाला जा सके।

भारतीय वाहन उद्योग के समक्ष कई तात्कालिक, मध्यम अवधि की चुनौतियां : आयुकावा

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय वाहन उद्योग गहरी संरचनात्मक सुस्ती से गुजर रहा है और कोविड-19 महामारी ने इस उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसे कई साल पीछे धकेल दिया है। सोयायटी ऑफ इंडियन ऑटोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष केनिची आयुकावा ने बुधवार को यह बात कही। सियाम के 61वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आयुकावा ने कहा कि पिछले 5 से 10 साल में सभी वाहन खंडों.....यात्री वाहनों से लेकर दोपहिया तक वृद्धि दर में जबर्दस्त गिरावट आई।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आयुकावा ने ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि कोविड महामारी शुरू होने से पहले ही भारतीय वाहन उद्योग संरचनात्मक सुस्ती से जूझ रहा था। आयुकावा ने कहा कि उद्योग के चारों खंडों....यात्री वाहन, दोपहिया, वाणिज्यिक वाहन और तिपहिया..में पिछले 5 से 10 साल के दौरान दीर्घावधि की वृद्धि दर में भारी गिरावट आई है। यह गिरावट महामारी से पहले शुरू हो गई थी।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से उद्योग और अधिक प्रभावित हुआ है। इससे उद्योग संख्या के लिहाज से कई साल पीछे चला गया है। आयुकावा ने कहा कि उद्योग इस समय कई तात्कालिक और मध्यम अवधि की चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि तात्कालिक चुनौतियों में.....महामारी से जुड़ी अनिश्चितताएं और हमारे लोगों का स्वास्थ्य, वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी, जिसों के बढ़ते दाम, आगामी ईंधन दक्षता तथा भारत चरण छह के तहत चरण-दो के नियमन, कंटेनरों की कमी और आयात अंकुश शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा उद्योग के समक्ष कई मध्यम अवधि की चुनौतियां मसलन मांग को कायम रखना, उपभोक्ताओं के लिए लागत को कम रखना, स्थानीयकरण, दीर्घावधि के नियमनों के लिए तैयारी और नई पावरट्रेन प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

अप्रैल-जून तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 18.5% रहने का अनुमान

SBI रिपोर्ट में किया गया खुलासा

नई दिल्ली। देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 18.5 प्रतिशत रहेगी। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप में यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि, यह भारतीय रिजर्व बैंक के अप्रैल-जून तिमाही के 21.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे नाउकास्टिंग मॉडल के अनुसार पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 18.5 प्रतिशत (ऊपर की ओर झुकाव के साथ) रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में हालांकि स्पष्ट किया गया है कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ऊंची वृद्धि दर की वजह पिछले साल का निचला आधार प्रभाव है। भारतीय स्टेट बैंक ने 41 उच्च चक्रीय संकेतकों के साथ नाउकास्टिंग मॉडल विकसित किया है। ये संकेतक औद्योगिक गतिविधियों, सेवा गतिविधियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पहली तिमाही में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 15 प्रतिशत रहेगा। इसमें कहा गया है कि कंपनियों के पहली तिमाही के जो नतीजे आए हैं उनसे पता चलता है कि कॉरपोरेट जीवीए इबीआईडीटीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व आय, जमा कर्मचारी लागत) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इकोरैप में कहा गया है कि पहली तिमाही में 4,069 कंपनियों के कॉरपोरेट जीवीए में 28.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, यह 2020-21 की चौथी तिमाही की वृद्धि से कम है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विश्व स्तर पर यह देखा गया है कि कम गतिशीलता से जीडीपी कम होती है और उच्च गतिशीलता उच्च जीडीपी की ओर ले जाती है, लेकिन यहां प्रतिक्रिया विषम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गतिशीलता घटने से आर्थिक गतिविधियां भी कम हुईं और इसके परिणामस्वरूप जीडीपी वृद्धि पर भी असर पड़ा, लेकिन गतिशीलता में वृद्धि होने पर भी जीडीपी वृद्धि उस अनुपात में नहीं बढ़ी। अल्ट्राहाई-फ्रिक्वेंसी इंडीकेटर्स पर आधारित बिजनेस एक्टीविटी इंडेक्स अगस्त 2021 में वृद्धि को दिखाता है। 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह के लिए नवीनतम रीडिंग में यह 103.3 रहा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के आंकड़ों, बिजली उपभोग के साथ गतिशीलता संकेतकों में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सुधार के संकेत मिलते हैं। इससे आगे आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक सुधार आने की पूरी उम्मीद है।

LIC का बंद हो चुकी पॉलिसी बहाल करने का अभियान, विलंब शुल्क में मिलेगी छूट

मुंबई। एजेंसी

अपने पॉलिसी धारकों को जोखिम कवर देने की निरंतर कोशिश में लगी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सोमवार को उन व्यक्तिगत पॉलिसी को दोबारा चालू करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान शुरू किया जो कि बीच में बंद हो गईं। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस विशेष अभियान के तहत, विशिष्ट पात्र योजनाओं की पॉलिसी को पहली बार प्रीमियम का भुगतान ना किए जाने की तिथि से पांच साल के भीतर दोबारा चालू किया जा सकता है और यह कुछ नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।

विज्ञप्ति के मुताबिक यह अभियान 23 अगस्त, 2021 से 22 अक्टूबर, 2021 तक चलेगा। इसमें कहा गया कि वैसी पॉलिसी जो प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान बंद हो गयीं और पॉलिसी अवधि को पूरा नहीं किया, वे इस अभियान के तहत दोबारा चालू किए जाने की पात्रता रखती है। विज्ञप्ति में कहा गया, 'अभियान उन पॉलिसीधारकों के लाभ के लिए शुरू किया गया है जिनकी पॉलिसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान ना कर पाने के कारण बीच में ही बंद हो गयी।'

बीमा निगम सावधिक आश्वासन और ऊंचे जोखिम की योजनाओं को छोड़कर अन्य पॉलिसी के मामले में विलंब शुल्क में रियायत की पेशकश कर रही है। यह कुल भुगतान किये गये प्रीमियम पर निर्भर करेगा। विज्ञप्ति के मुताबिक किसी पॉलिसीधारक को यदि एक लाख रुपये का प्रीमियम देना है तो उसे विलंब शुल्क में 20 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी, इसमें अधिकतम छूट 2,000 रुपये तक होगी। इसी प्रकार बंद पॉलिसी को चालू करने में यदि एक लाख रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक का प्रीमियम देना है तो कंपनी इसमें विलंब शुल्क में 25 प्रतिशत और अधिकतम 2,500 रुपये की छूट देगी। इससे अधिक प्रीमियम के भुगतान में विलंब शुल्क में 30 प्रतिशत और अधिकतम 3,000 रुपये तक की छूट दी जायेगी।

भारत इलेक्ट्रिक परिवहन व्यवस्था की ओर अग्रसर, उद्योग को लाना होगा बदलाव : अमिताभ कांत

नई दिल्ली। एजेंसी

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा है कि वाहन क्षेत्र में बदलाव आना तय है और अब हम इलेक्ट्रिक परिवहन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारत को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अगुवा बनाने के लिए बदलाव लाने का काम वाहन उद्योग को करना है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि अगले दो साल के दौरान बैटरियों के दाम और नीचे आएंगे। इससे उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी। उन्होंने कहा, "नीति आयोग में हम वाहन क्षेत्र में इनोवेशन, दक्षता तथा निवेश को प्रोत्साहन के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। इससे विशेषरूप से उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शुरुआती अग्रिम लागत कम होगी। मैं इलेक्ट्रिक वाहनों पर इसलिए जोर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यह बदलाव अपरिहार्य है।"

कांत ने कहा कि हम कॉम्पैक्ट कार विनिर्माण का केंद्र है। यदि हम इनोवेशन नहीं करेंगे और बदलाव नहीं लाएंगे, तो हम इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण में सबसे आगे रहने का अवसर गंवा देंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर बैटरियों के दाम उम्मीद से ज्यादा तेजी से घट रहे हैं, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें उपभोक्ताओं के लिए नीचे आएंगी। उन्होंने कहा कि अगले दो साल में बैटरियों के दाम और घटेंगे। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि देश में दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया, वाणिज्यिक वाहनों के साथ लंबी दूरी के वाहनों का 'चैंपियन' बनने की क्षमता है। कांत ने वाहन विनिर्माताओं से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को समर्थन देने के लिए शोध और विकास में निवेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत मूल्य की दृष्टि से संवेदनशील बाजार है। ऐसे में इनोवेटिव कारोबारी विकल्प मसलन बैटरी की अदला-बदली और लीजिंग से इसकी लागत घटेगी। कांत ने कहा कि भारत में बैटरी विनिर्माण में भी अगुवा बनने की क्षमता है।

वित्त मंत्रालय बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में बीमा बांड लाने पर कर रहा विचार

मुंबई। एजेंसी

वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने मंगलवार को कहा कि सरकार बैंक गारंटी के विकल्प के तौर पर बीमा बांड पेश करने पर विचार कर रही है। सोमनाथन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उद्योग प्रमुखों की बैठक के दौरान यह घोषणा की। सीतारमण दो दिन के मुंबई दौरे पर हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, "सरकार बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में बीमा बांड लाने पर विचार कर रही है।" बैंक गारंटी आमतौर पर ऋण देते समय मांगी जाती है और सामान्य रूप से गिरवी संपत्ति के तौर पर इसकी जरूरत होती है। एक बीमा बांड भी गारंटी की तरह है लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की रहन की आवश्यकता नहीं होती। उद्योग प्रमुखों के साथ बैठक में सीतारमण ने कहा कि सरकार नीतियों के मामले में निश्चितता और भरोसे को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नियामकों की भी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियामकों के साथ काम कर रही है। इस मौके पर राजस्व सचिव तरूण बजाज ने कहा कि विभाग स्टार्टअप के कर संबंधित मुद्दों पर काम कर रहा है। उन्होंने इस बारे में उद्योगों से सुझाव मांगे। सीतारमण ने उद्योग को बिजली की उच्च दर समेत प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले और जटिल नियामकीय अनुपालनों के मुद्दों के समाधान का आश्वासन भी दिया। वित्त मंत्री बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करने वाली हैं।

अच्छी खबर: ईएसआईसी में आ सकते हैं 30 हजार रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी

नई दिल्ली। एजेंसी

राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) की मेडिकल स्कीम का दायरा बढ़ाकर 30 हजार रुपये वेतन तक करने की तैयारी है। फिलहाल 21 हजार रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी ही इसमें आते हैं। नया प्रस्ताव ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा। मंजूरी के बाद इसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।

ईएसआईसी बोर्ड के सदस्य हरभजन सिंह ने आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान को बताया कि सदस्यों ने पहले ही केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को सीलिंग बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया है। इस मेडिकल स्कीम से कोरोना काल में कर्मचारियों को खासा फायदा हुआ है। वेतन सीमा बढ़ने से देश में और 20-25 फीसदी कर्मचारी इस दायरे में आ जाएंगे। ईएसआईसी बोर्ड की बैठक सितम्बर में प्रस्तावित है। इसी में प्रस्ताव रखा जाएगा। वेतन सीमा बढ़ने से ईएसआईसी का फंड बढ़ेगा। साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज भी मिल सकेगा।

बोर्ड सदस्य के अनुसार, इस समय ईएसआईसी योजना के सदस्य के वेतन से 0.75 फीसदी तो नियोक्ता से 3.25 फीसदी अंश लिया जाता है। पहले यह अंशदान 6.5 फीसदी था। देश में 6 करोड़ कर्मचारी इसके दायरे में हैं। यूपी में 22 लाख कामगारों ईएसआईसी मेडिकल स्कीम का लाभ मिलता है।

ईएसआईसी योजना के तहत मिलने वाले लाभ

इस समय ईएसआईसी बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक अशक्तता की स्थिति में उसके पति/पत्नी एवं विधवा मां को जीवन पर्यंत और बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक उस कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर पेंशन दिया जाता है। कर्मचारी की बेटी होने की स्थिति में उसे उसकी शादी तक यह लाभ दिया जाता है। ईएसआईसी योजना के तहत बीमा धारक या बीमित व्यक्ति के परिवार के सभी आश्रित सदस्य, जो ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल में कोविड बीमारी के निदान और इस रोग के कारण बाद में मौत से पहले पंजीकृत हैं, वे भी काम के दौरान मरने वाले बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को प्राप्त होने वाले लाभ और इसे समान स्तर पर ही हासिल करने के हकदार हैं। इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होंगी।

पहली कि आईपी को ईएसआईसी ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड रोग के निदान और इसके चलते होने वाली मौत से कम से कम तीन महीने पहले पंजीकृत होना चाहिए। दूसरी कि बीमित व्यक्ति निश्चित तौर पर वेतन के लिए नियोजित होना चाहिए और मृतक बीमित व्यक्ति के संदर्भ में कोविड रोग का पता चलने, जिससे मौत हुई हो, ठीक पूर्ववर्ती एक साल के दौरान कम से कम 78 दिन का अशंदान होना चाहिए।

बीमित व्यक्ति, जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और कोविड बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, उनके आश्रित अपने जीवन के दौरान बीमित व्यक्ति के औसत दैनिक वेतन का 90 फीसदी मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह योजना 24 मार्च, 2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। ईपीएफओ की कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत इस योजना के सदस्य की मौत होने पर उनके परिवार के सभी जीवित आश्रित सदस्य ईडीएलआई के लाभों को हासिल करने के योग्य होंगे।

ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की जरूरत नहीं

वर्तमान में इस योजना के तहत, कर्मचारी की मौत के मामले में दिए गए लाभों का विस्तार किया गया है, अब ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की जरूरत नहीं है, पारिवारिक पेंशन का भुगतान ईपीएफ और एमपी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है, कर्मचारी के बीमार होने और कार्यालय न आने की स्थिति में साल में 91 दिनों के लिए बीमारी लाभ के रूप में कुल मजदूरी का 70 फीसदी का भुगतान किया जाता है। मृतक कर्मचारी के परिजनों को मिलने वाली अधिकतम लाभ राशि को छह लाख से बढ़ाकर सात लाख कर दिया गया है। मृतक कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ मिलेगा, जो अपनी मौत से पहले एक या अधिक प्रतिष्ठानों में 12 महीने की निरंतर अवधि के लिए सदस्य थे। मौजूदा प्रावधान में एक प्रतिष्ठान में 12 महीने तक लगातार रोजगार का प्रावधान है।

एचडीएफसी लाइफ ने एचडीएफसी लाइफ सरल पेंशन लॉन्च किया

सिंगल प्रीमियम, नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत की अग्रणी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक, एचडीएफसी लाइफ ने सिंगल प्रीमियम, नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट, एचडीएफसी लाइफ सरल पेंशन, लॉन्च करने की घोषणा की है, जो खरीद के समय ही आजीवन गारंटीयुक्त वार्षिकी दरों का ऑफर देता है। एचडीएफसी लाइफ सरल पेंशन एक स्टैंडर्ड व्यक्तिगत, तत्काल एन्युइटी प्रोडक्ट है, जिसके आसान फीचर्स और स्टैंडर्ड नियम एवं शर्तें हैं, और जो ग्राहकों को उनकी सेवानिवृत्ति की योजना के लिए जानकारी आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सरेन्डर की स्वीकृति पर, करों को छोड़कर, खरीद मूल्य का 95 प्रतिशत, एन्यूइटैंट को भुगतान किया जाएगा, जो बकाया लोन राशि और लोन ब्याज, यदि कोई हो, तो उसकी कटौती के अधीन है। भारत में सामाजिक सुरक्षा के अभाव को देखते हुए एन्युइटी एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट श्रेणी है। यह व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद भी नियमित आय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। जीवनकाल में वृद्धि, हेल्थकेयर सुविधाओं में सुधार और एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति, ये सभी कारक सेवानिवृत्ति योजना की आवश्यकता पर जोर देते हैं। एन्युइटी योजनाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद भी आरामदायक जिन्दगी गुजारता रहे। लॉन्च के बारे में बताते हुए, श्रीनिवासन पार्थसारथी, चीफ एक्चुअरी, एचडीएफसी लाइफ ने कहा कि 'एन्युइटी योजनाएं उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु नजदीक है या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये योजनाएं बाजार की अस्थिरताओं और गिरती ब्याज दरों के मुकाबले सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर सकती हैं। प्रोडक्ट को खरीदने के तुरंत बाद ही, व्यक्ति को नियमित भुगतान मिलना शुरू हो जाता है जो उनके शेष जीवन के लिए लॉक-इन एन्युइटी दरों के साथ स्थिर और नियमित आय सुनिश्चित करता है। एचडीएफसी लाइफ सरल पेंशन सरल और समझने में आसान प्रोडक्ट है। यह सेवानिवृत्ति योजना के मामले में सहायक साधन है और हम उम्मीद करते हैं कि ग्राहक इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे।'एचडीएफसी लाइफ सरल पेंशन किसी व्यक्ति के लिए यह चुनने की सुविधा प्रदान करता है कि कोई व्यक्ति एन्युइटी कैसे प्राप्त करे – यानी कोई इसे मासिक, त्रैमासिक, द्वि-वार्षिक या वार्षिक रूप से प्राप्त करना चुन सकता है। इसके अलावा, जॉइंट लाइफ ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने जीवनसाथी को लाभ देना चाहते हैं।

निवेशकों की सुविधा के फिनोलॉजी वन के तहत प्रीमियम सेवाओं की घोषणा

फाइनेंशियल प्लानिंग टूल, लर्निंग प्लेटफॉर्म और इक्विटी रिसर्चटूल का कलेक्शन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना इतना आसान इससे पहले कभी नहीं रहा और फिनोलॉजी ने इसे और आसान बना दिया है। भारतीय निवेशकों को अपनी निवेश यात्रा शुरू करने में सशक्त बनाते हुए भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल एजुकेशन और वन-स्टॉप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फिनोलॉजी ने सब्स्क्रिप्शन-बेस्ड मॉडल- फिनोलॉजी वन के तहत प्रीमियम सेवाओं को लॉन्च किया है। किफायती सॉल्युशन विशेष रूप से विशेषज्ञों ने तैयार किए हैं। फिनोलॉजी वन में आपको एक ही जगह पर कई फाइनेंशियल्स टूल्स मिलेंगे, जैसे- रेसिपी, क्वेस्ट और टिकर। यह न केवल यूजर्स की फाइनेंशियल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि उन्हें विभिन्न साधनों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। एक सब्स्क्रिप्शन लेकर यूजर सिर्फ 499 रुपए प्रतिमाह की लागत पर सभी प्रीमियम टूल्स तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। विकास पर बोलते हुए, प्रांजल कामरा, प्रवक्ता और सीईओ, फिनोलॉजी, ने कहा, 'वित्तीय योजना बनाना और सीखना भारत में बहुत ही महंगा और जटिल है। हम चाहते हैं कि हमारे यूजर्स को निवेश का सहज अनुभव मिले। इस वजह से हमने उन्हें उन साधनों तक पहुंच प्रदान की है जो किफायती और परेशानी मुक्त हैं। फिनोलॉजी वन का उपयोग कोई भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आसानी से कर सकता है – बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक।' अपने निवेशकों की वित्तीय जरूरतों को बुद्धिमान समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फिनोलॉजी वन को इस तरह तैयार किया गया है कि यह यूजर्स को एक सहज अनुभव प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म का इंटेलिजेंट फाइनेंशियल प्लानिंग टूल रेसिपी व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों के साथ निवेश को जोड़ने में मदद करता है। यह एक इंटिग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानर है जिसका उद्देश्य अपनी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट की सिफारिशों के माध्यम से निवेशकों को सशक्त बनाना है। फाइनेंशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म क्वेस्ट के साथ यूजर प्रासंगिक और स्पष्ट कोर्सेस के माध्यम से अपनी गति से निवेश और फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। यह यूजर्स कोप्री-डिजाइन जानकारी का रास्ता दिखाता है, जहां वे फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकते हैं। क्वेस्ट यूजर्स को प्रतिष्ठित बीएसई इंस्टीट्यूट और फिनोलॉजी सर्टिफिकेशन के साथ पुरस्कृत भी करता है जो निश्चित रूप से उनके प्रोफेशनल जीवन को बढ़ावा देगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।